



फास्ट News

तीसरी बार नजरबंद किया गया: महबूबा

आईएनएस, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को फिर आरोप लगाया कि उन्हें 15 दिनों में तीसरी बार गैरकानूनी तरीके से नजरबंद किया गया। उन्होंने टिवटर पर लिखा कि उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जबकि बीजेपी के मंत्रियों को जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनावों में प्रचार करने की अनुमति थी। मुफ्ती ने टीवीट किया, 'अवैध रूप से एक पखवाड़े से कम समय के भीतर तीसरी बार नजरबंद किया गया।'

मोदी से बोले KCR- नई संसद पर गर्व

आईएनएस, हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। पीएम को लिखे पत्र में कहा, 'मैं संसद विस्तार के भव्य प्रोजेक्ट के लिए आभारशिलता रखने के अक्सर पर गर्व के साथ आपसे जुड़ता हूँ। सीएम ने कहा कि राजधानी में मौजूदा संसद अपर्याप्त है और हमारे औपनिवेशिक अतीत से भी जुड़ा हुआ है।'

बंगाल के पूर्व CM हॉस्पिटल में भर्ती

भाषा, कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद बुधवार को अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों ने कहा कि अस्पताल के 'फ्लू क्लीनिक' में डॉक्टर माफ्या के वरिष्ठ नेता भट्टाचार्य का इलाज कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'उनका इलाज चल रहा है। हमारे फ्लू क्लीनिक में उनकी जरूरी जांच की जा रही है।' साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे भट्टाचार्य कुछ समय से सांस संबंधी दिक्कतों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं।

राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता, कहा- किसान कानून जल्दबाजी में बने

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला। उनसे सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध दूर करने के लिए विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे नेताओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी. राजा और डीएमके के सदस्य शामिल थे। राष्ट्रपति से मिलकर निकले विपक्षी दलों ने मीडिया से बात की। येचुरी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को बताया कि ये तीनों कानूनों अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में पास किए गए, इसलिए इन कानूनों को वापस लिया जाए।



बुधवार को विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला।

नई रणनीति बनाने के लिए जुटे मंत्री, अमित शाह से मिले गोयल और तोमर

विपक्षी नेताओं का कहना था कि सरकार किसानों की बातों को समझे। उनकी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द करे। वहीं, पवार का कहना था कि संसद में विपक्ष ने मांग की थी कि सरकार इन बिलों पर गहन चर्चा के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेजे, लेकिन सरकार ने विपक्ष के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। जल्दबाजी में बिलों को पास करा दिया। राहुल गांधी का कहना था कि जिस तरह से कृषि बिल पास किए गए, उससे लगता है कि यह किसानों का अपमान है, इसलिए वे उठंड के मौसम में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

राजस्थान में हमारी जीत कृषि कानूनों पर मुहर

पीटीआई, नई दिल्ली: बीजेपी ने बुधवार को राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में मिली सफलता को केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों पर किसानों की मुहर बताया। पार्टी ने कहा कि नतीजे बतलाते हैं कि मतदाता सभी जगह बीजेपी के पक्ष में हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना महामारी, वैश्विक आर्थिक संकट और कृषि सुधारों पर विपक्ष के दुष्प्रचार के बाद भी मतदाता सभी जगह बीजेपी को स्पंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में बीजेपी की जीत मिली है। जिला परिषद के इन चुनावों में 2.5 करोड़ मतदाताओं में से अधिकतर किसान हैं। इसका मतलब है कि किसान राजस्थान में कृषि सुधारों के पक्ष में हैं।'

विपक्ष, नई दिल्ली: सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसानों द्वारा नामंजूर किए जाने के बीच नई उपजी स्थिति के मद्देनजर बुधवार शाम मोदी सरकार के मंत्रियों की अहम मीटिंग हुई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहां हुई इस मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, तकररीबन दो घंटे चली मीटिंग में किसानों द्वारा सरकार के प्रस्ताव टुकटुकाने से जुड़े फैसले पर चर्चा और आगामी संभवनाओं और विकल्पों पर चर्चा हुई। इससे पहले सरकार ने कृषि कानूनों से जुड़ी किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए बुधवार को जो लिखित प्रस्ताव भेजा, उसे किसानों के नुमाइंदों ने नामंजूर कर दिया। इसी के साथ किसानों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता का अगला दौर टल गया। किसानों ने सरकार को अपना आंदोलन और तेज करने का अल्टीमेटम दिया। बता दें कि सरकार और किसानों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। बुधवार को दोनों पक्षों के बीच छठे दौर की मुलाकात होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजने के चलते मुलाकात टल गई थी।

कर्नाटक में पास हुआ गौ-हत्या के खिलाफ बिल

पीटीआई, बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के बीच गौ-हत्या के खिलाफ विवादाित विधेयक पेश हो गया। कांग्रेस ने इसके खिलाफ संसद का बहिष्कार किया। विधेयक में पूरे राज्य की बात कही गई है। वहीं, गायों की अवैध तस्करी, अत्याचार और हत्या करने पर सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने बताया, 'हां, विधानसभा में विधेयक पास हो गया है।' इसमें गाय और बछड़ों के अलावा 12 साल से छोटे भैंस और उनके बच्चों की हत्या पर रोक की बात कही गई है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल आदिवासियों को सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाने का भी प्रावधान है।

नड्डा का 'मिशन बंगाल' शुरू, दिखाए गए काले झंडे

पीटीआई, कोलकाता: बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा बुधवार को दो दिवसीय दौर पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। हालांकि, उनके कोलकाता पहुंचते ही विरोध शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए गए और उनके खिलाफ 'वापस जाओ-वापस जाओ' के नारे लगाए। राज्य के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी के व्यापक जन संघर्ष अभियान के तहत नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पार्षद होने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य में 200 से ज्यादा सीटों के साथ अगली सरकार बनाने का भरपूर जताया। नड्डा ने टीएमसी सरकार पर अल्पसंख्यक तुट्टिकरण का आरोप लगाया।

शोकाभूषण की अगुआई वाली बेंच इस मामले में 25 जनवरी से सुनवाई करेगी। पांच जजों की संवैधानिक बेंच मामले में विचार करेगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से गृहार्हण लाई ऑफ आदेश 9 सितंबर के रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस

'असहिष्णुता' का दूसरा नाम ममता बनर्जी: बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 'असहिष्णुता' का पर्याय होने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य में 200 से ज्यादा सीटों के साथ अगली सरकार बनाने का भरपूर जताया। नड्डा ने टीएमसी सरकार पर अल्पसंख्यक तुट्टिकरण का आरोप लगाया।

मराठा आरक्षण पर रोक हटाने से कोर्ट का इनकार

विपक्ष, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरों और शिक्षण संस्थाओं में मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक का फैसले बदलने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बांबें हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस

दोष साबित होने पर रोक नहीं, तो चुनाव नहीं लड़ सकते: SC

पीटीआई, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपाधिक मामले में दोषी को दो साल या इससे ज्यादा की सजा होती है और अगर उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की एकलुप्तम सीट पर निर्वाचन अधिकारी ने सरिता एस नायर का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया था। इस पर सरिता ने फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। निर्वाचन अधिकारी ने केरल में सौर घोटाले से संबंधित आपाधिक मामले में नायर को दोषी ठहराए जाने और उसे

सजा होने के तथ्य के मद्देनजर उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की पीठ ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि उसका नामांकन पत्र निरस्त करना गलत था, क्योंकि उसकी तीन साल की सजा को अपील अदालत ने सस्पेंड कर दिया था। पीठ ने कहा कि सजा को सस्पेंड करना दोषसिद्धि की स्थिति नहीं बदलता।

सूत्रों ने कहा कि 'फ्लू क्लीनिक' में डॉक्टर माफ्या के वरिष्ठ नेता भट्टाचार्य का इलाज कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'उनका इलाज चल रहा है। हमारे फ्लू क्लीनिक में उनकी जरूरी जांच की जा रही है।' साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे भट्टाचार्य कुछ समय से सांस संबंधी दिक्कतों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि अस्पताल के 'फ्लू क्लीनिक' में डॉक्टर माफ्या के वरिष्ठ नेता भट्टाचार्य का इलाज कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'उनका इलाज चल रहा है। हमारे फ्लू क्लीनिक में उनकी जरूरी जांच की जा रही है।' साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे भट्टाचार्य कुछ समय से सांस संबंधी दिक्कतों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं।

त्रिपुरा में खलबली, CM ने की नड्डा से बात

समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं यह पार्टी हाईकमान को सूचित कर दूंगा। जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के त्रिपुरा इंचार्ज विनोद सोनकर ने सीएम से बातचीत की। माना जा रहा है कि बातचीत के बाद ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। त्रिपुरा बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अक्टूबर में बीजेपी के करीब 9 विधायक दिल्ली पहुंचे और सीएम बिनल देव को हटाने की मांग की। कुछ दिन पहले जब त्रिपुरा के नए पार्टी प्रभारी विनोद सोनकर त्रिपुरा पहुंचे तो वहां मीटिंग हॉल के बाहर बिलबल हड़ाओ, बीजेपी बचाओ की नारेबाजी हुई। मंत्रालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीएम बिनल देव देव से इस नारेबाजी के बारे में पूछा गया तब उन्होंने इमोशनल होकर कहा कि वह 13 दिसंबर को जनता से पूछे कि मैं सीएम रहूँ या नहीं।

NBT SMART JOBS नवभारत टाइम्स Consumer Connect Initiative

JOBS अलर्ट वेबसाइट: sssc.uk.gov.in • मैनेजर संस्थान: एयरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया पद का नाम: मैनेजर समेत कई पद पदों की संख्या: 368 आखिरी तारीख: 14 जनवरी वेबसाइट: aai.aero • डाटा एंट्री ऑपरेटर संस्थान: मध्य प्रदेश प्रफेशनल एजामिनेशन बोर्ड पद का नाम: डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई पद पदों की संख्या: 258 आखिरी तारीख: 14 दिसंबर वेबसाइट: peb.mp.gov.in • आर्मी संस्थान: इंडियन आर्मी पद का नाम: सिपाही (जनरल) पदों की संख्या: 854 आखिरी तारीख: 24 दिसंबर

इंजिनियरिंग पदों की संख्या: जारी नहीं आखिरी तारीख: 7 जनवरी वेबसाइट: joinindianarmy.nic.in • अग्रेजी संस्थान: 5 आखिरी तारीख: 31 दिसंबर वेबसाइट: nwda.gov.in • नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पद का नाम: इंजिनियर पदों की संख्या: 70 आखिरी तारीख: 12 दिसंबर वेबसाइट: ntpccareers.net

टीचिंग 1. संस्थान: वल्लभभाई पटेल संस्थान पद का नाम: टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पद पदों की संख्या: 71 आखिरी तारीख: 13 दिसंबर वेबसाइट: vpci.org.in 2. संस्थान: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पद का नाम: अग्रेजी प्रोफेसर के कई पद पदों की संख्या: 328 आखिरी तारीख: 24 दिसंबर

एग्जाम कैलेंडर SSC-Const. Delhi Police 11&14 दिसंबर 2020 ssc.nic.in EPFO Social Security Asst 25 दिसंबर 2020 epfindia.gov.in BIS Asst Director 24 दिसंबर 2020 bis.gov.in IBPS SO (Pre Exam) 26-27 दिसंबर 2020 ibps.in

WALK-IN INTERVIEW आवश्यकता है सेल्फ प्रोफेशनल और ररिथा सेल्फ मैनेजर की- दिनांक: 09 से 12 दिसंबर, 2020 समय: प्रातः 10:00 बजे से सां. 5:00 तक • आर्मी संस्थान: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पद का नाम: सहायक समाज कल्याण अधिकारी समेत कई पद पदों की संख्या: 854 आखिरी तारीख: 24 दिसंबर

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नवरत्न वर्ग का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारत की अग्रणी पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को इसकी केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु के लिए सविदा आधार पर 01 (एक) प्रशिक्षु राजभाषा अधिकारी (अनुवादक) की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.bel-india.in पर CAREERS लिंक देखें। दिनांक - 09.12.2020 पबंधक (एच.आर. एंड ए) फोन : 080 28385617

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) का उद्यम ईसीआईएल (पी. ), हैदराबाद - 500 062, तेलंगाना • इंजीनियरिंग पदों की संख्या: 5 आखिरी तारीख: 31 दिसंबर वेबसाइट: vpci.org.in

Park Hospital Advanced Super Speciality The Signature HOSPITAL OPPORTUNITY TO BE A PART OF THE FASTEST GROWING CHAIN OF SUPER SPECIALITY HOSPITALS OF NORTH INDIA HIRING for a position of CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) A person should have at least 10 years of experience, Sound knowledge of Fund Management, Fund Raising, Internal Audit, Banking and Taxation Salary- Rs. 2.5- Rs. 5.0 Lakhs/Month

RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE BANDA ATARRA, BANDA - 210201 Advt. No: 01/Dir/RECBanda/2020 APPOINTMENTS Date: 08.12.2020 Applications are invited for the post of Director, Rajkiya Engineering College Banda, Atarra, Banda-210201 [U.P.] in the pay matrix of Level-14, Entry pay Rs. 144,200/- and allowances as admissible under Government orders. The post shall be contractual in nature for 5 years. Qualification and Experience: The Qualification and Experience for the post shall be as per AICTE Regulation notified on 01 March 2019 (as amended from time to time by AICTE). For details please visit the college website: www.recbanda.ac.in

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पालिका केन्द्र : नई दिल्ली सेक्रेटरी/ज एस्टेबलिशमेंट ब्रांच अंतिम (कट ऑफ) तिथि का विस्तार विषय: प्रतिनिधित्व आधार पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में संयुक्त निर्देशक के 03 पदों, संशोधन-पूर्व वृत्तमान पीबी-3, रु.15600-39100 + ग्रेड पे रु. 6600/- (संशोधन-पूर्व) सहित, 7 वे सीपीसी में लेवल 11 के लिए संशोधित-अंतिम तिथि का विस्तार। रिक्ति संकुलर एसओ (ई)/772एसए-1(आर)/2020 दिनांक 21.10.2020 की निरन्तरता में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में संयुक्त निर्देशक के पद हेतु आवेदन प्रपत्र की अंतिम तिथि 21.12.2020 तक विस्तारित की जाती है। हस्ता./- (आर.पी. सति) निर्देशक (कार्यिक)